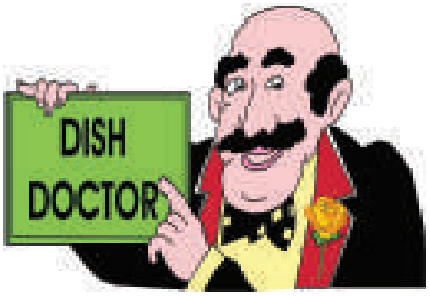
DISH DOCTOR



Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or
Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

LINEAR TV DISTRIBUTION

Q: How will TRAI's proposed authorisation framework for internet-based linear TV distribution impact traditional DTH and cable operators, and what technical challenges will it create for service providers?

Dinkar Reddy, Cable TV Consultant, Bengaluru

Ans.: The proposed framework represents an important step towards bringing internet-based linear television distribution within India's broadcasting regulatory structure. Traditionally, DTH and cable operators have operated under specific authorisations, while several applications offering live television channels over the internet have functioned under a different regulatory environment. TRAI's recommendations seek to address this disparity through a technology-neutral approach.

From a technical standpoint, Application-Based Linear Television Distribution (ALTD) will rely on IP networks to deliver scheduled television channels through smart TVs, mobile devices, streaming devices and web browsers. Unlike conventional DTH, which uses satellite infrastructure, or cable television, which relies on a dedicated distribution network, ALTD uses broadband connectivity and internet-based delivery systems.

However, service reliability remains a major consideration. Unlike dedicated broadcast networks, internet delivery is affected by available bandwidth, network congestion, latency and variations in broadband quality. Consistent picture quality, minimal buffering, content security and scalable content delivery networks will therefore be essential for delivering a television-like experience.

TRAI's October 2026 recommendations propose a distinct authorisation category for ALTD services. They also envisage a central repository of authorised applications, compliance obligations for device manufacturers and operating system providers, and consumer grievance redressal mechanisms. These measures could improve accountability and consumer protection.■

लीनियर टीवी वितरण

प्रश्नः इंटरनेट-आधारित लीनियर टीवी वितरण के लिए ट्राई का प्रस्तावित ऑथराइजेशन ढ़ांचा, पारंपरिक डीटीएच और केबल ऑपरेटरों को कैसे प्रभावित करेगा? साथ ही, इससे सेवा प्रदायकों के सामने किस तरह की तकनीकी चुनौतियां आयेंगे?

दिनकर रेड्डी, केबल टीवी कंसल्टेंट, बंगलुरू

उत्तरः प्रस्ताावित ढ़ांचा, इंटरनेट आधारित लीनियर टेलीविजन को भारत के प्रसारण नियामक ढ़ांचे के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक रूप से, डीटीएच और केबल ऑपरेटर, विशिष्ट प्राधिकरणों के तहत काम करते रहे हैं, जबकि इंटरनेट के जरिए लाइव टेलीविजन चैनल उपलब्ध कराने वाले कई आवेदन एक अलग नियामक माहौल में काम करते हैं। ट्राई की सिफारिशें एक 'टेक्नोलॉजी न्यूट्रल' दृष्टिकोण अपना कर इस अंतर को दूर करने का प्रयास करती हैं।

आमतौर पर तकनीकी दृष्टिकोण से, एप्लीकेशन बेस्ड लीनियर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन (एएलडीटी) निर्धारित समय पर प्रसारित होने वाले टेलीविजन चैनलों को स्मार्ट टीवी, मोबाइल उपकरण, स्ट्रीमिंग उपकरण और वेब ब्राउजर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए आईपी नेटवर्क पर निर्भर करेगा। पारंपरिक डीटीएच, जो सैटेलाइट संरचना का उपयोग करती है, या केबल टेलीविजन, जो एक समर्पित वितरण नेटवर्क पर भिर करता है, के विपरीत, एएलटीडी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इंटरनेट आधारित वितरण प्रणालियों का उपयोग करता है।

हालांकि, सेवा की विश्वनीयता एक अहम पहलू बनी हुई है। समर्पित प्रसारण नेटवर्कों के विपरीत, इंटरनेट के जरिए कंटेंट की डिलीवरी उपलब्ध बैंडविड्थ, नेटवर्क पर भीड़, लेटेंसी और ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकती है। इसलिए, टीवी जैसा अनुभव देने के लिए एक जैसी पिक्चर क्वालिटी, कम से कम बफरिंग, कंटेंट की सुरक्षा और स्केलेबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का होना जरूरी होगा।

ट्राई की अक्टूबर **2026** की सिफारिशों में एएलटडी सेवाओं के लिए एक अलग ऑथराइजेशन कैटगरी का प्रस्ताव है। इनमें अधिकृत आवेदन का एक केंद्रीय रिपॉजिटरी, उपकरण निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं के लिए अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियां और उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण की व्यवस्था शामिल है। इन उपायों से जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण में सुधार हो सकता है।■